राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ

जनसत्ता बादशाह

www.picmp.com

आरएनआई निबंधन संख्या-एमपीएचआईएन-1999/4107

डाक पंजीयन-म.प्र./भोपाल/371/2012-14

वर्ष-13,अंक-18 (अठारह सालों से प्रकाशित) भोपाल, मंगलवार 14 मई 2013 मूल्य पांच रुपया

क्या राजपुत्रों के हित में फिर कटेगा एकलव्य का अंगूठा

आदिवासी मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी गहरा षड़यंत्र

-आलोक सिंघई-

मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल से व्यापक जनाधार वाले आदिवासी विधायक विजय शाह को हटाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर सवर्णों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का तुष्टिकरण करने की कोशिश की है। उनके इस कदम से जहां मध्यप्रदेश का आदिवासी समुदाय अचंभित है वहीं प्रतिपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। खुद विजय शाह इस मामले में ज्यादा नहीं बोलना चाहते वे कहते हैं कि हमने सिर्फ चरैवेति चरैवेति के संस्कार पाए हैं इसलिए अपने मतदाताओं और आदिवासियों के हितरक्षण के लिए हमेशा काम करते रहेंगे।

कुंवर विजय शाह को मंत्रिमंडल से निष्कासित करने का आधार न्यूज चैनलों की खबरें और अखबारों की टिप्पणियां बनी। छात्राओं के बीच हुए एक कार्यक्रम में विजय शाह ने सहज संवाद स्थापित करने के लिए जो बातें कहीं वे उनकी विदाई की वजह बन गईं। देवर भाभी का चुटीला संवाद उनकी विदाई की वजह बन गया। उनके शब्दों को कुत्सित मानसिकता वाले घटिया मजाक का रंग दे दिया गया।

मकड़ाई रियासत के नरेश और आदिवासियों के बीच लोकप्रिय जन नेता विजय शाह पत्रकारों के बीच भी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश में सत्तासीन होने के लिए हाथ पांव मार रही थी तब विजय शाह जैसे जमीनी नेता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भ्रष्ट दिग्विजय सिंह सरकार से दो दो हाथ कर रहे थे। विधानसभा क्षेत्र हरसूद में विजय शाह के साथ प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों को दिग्विजय सिंह की पुलिस ने खदेड़कर पीटा था। उस प्रदर्शन से उपजी सहानुभूति ने विजय

शाह को सितारा बना दिया और तबसे लेकर अब तक उनकी लोकप्रियता लगातार परवान चढ़ी है। समाचार पत्रों ने भी उनकी राजनीतिक कार्यशैली को अपना समर्थन दिया और मकड़ाई नरेश धीरे धीरे प्रदेश की आदिवासियों की राजनीति का प्रतीक बन गए।

उनकी इस राजनीतिक यात्रा में धर्मपत्नी भावना शाह ने आगे बढ़कर साथ दिया। खंडवा की महापौर रहते हुए उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी और जब विजय शाह और भावना शाह की जुगलबंदी ने लोकप्रियता के नए आयाम रचे तो सत्ता पुत्रों के माथों पर शिकन बढ़ने लगी। नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर को पट्टी पढ़ाकर नगर निगम खंडवा में एक ऐसे कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई जो केवल अडंगे लगाने में विशेषज्ञ था। भावना शाह के खिलाफ स्थानीय अखबारों में खबरें छपने लगीं। बेटे की गतिविधियों पर सवालिया निशान लगाने की मुहिम भी इसी कूटनीतिक चाल का नतीजा थी।

दरअसल विजय शाह का निष्कासन मध्यप्रदेश के मूल निवासियों यानि आदिवासियों पर पहला प्रतिघात नहीं है। मध्यप्रदेश के स्थापना काल से लेकर अब तक आदिवासी नेताओं को वोट बटोरने वाले हरकारों की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। आदिवासियों की इस राजनीति को तराशने वाले कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने आदिवासी नेताओं को सत्ता का सपना दिखाया और फिर धीरे से कुर्सी खुद हड़प ली। चाहे वे शिवभानुसिंह सोलंकी हों या फिर महेन्द्र कर्मा। यही कारण है कि आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद ने सबसे पहले कदम जमाए।

इधर भाजपा ने भी आदिवासी नेताओं की गर्दन मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

(शेष पेज 7 पर पढ़िए)

प्रजातंत्र में ठेंगा दिखाएगा राजतंत्र का अंगूठा

द्वापर युग में भले ही गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आदिवासी एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया हो पर प्रजातंत्र में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विजय शाह ने उनकी आर्थिक प्रगति पर ज्यादा जोर दिया। आदिवासी मंत्री की पहल पर लगभग बारह जिलों में आदिवासियों को संरक्षण देने वाले बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ। शेष जिलों में भी ये विस्तार होना बाकी है। विजय शाह के इन जमीनी प्रयासों ने ही भाजपा के सत्ताधीशों के कान खड़े कर दिए और अधकचरा शिकायतों के आधार पर विजय शाह की मंत्रिमंडल से विदाई कर दी गई। आगामी 25 मई को एनसीपी ने मंडला में आदिवासी संगम बुलाया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता भी इस संगम में पहुंच रहे हैं। आदिवासी अस्मिता की चिंगारी और सुलगती है तो कोई आश्चर्य नहीं कि अंगूठा मांगने का ख्वाब देखने वाले भाजपाई रणनीतिकारों को वही अंगूठा ठेंगा भी साबित हो सकता है।-**पं.अनिल तिवारी**

सैडमेप के कर्मचारियों के शोषण पर भाजपा के दिग्गजों की चुप्पी

भोपाल। बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकारें खाली बैठे हाथो को काम नहीं दे पा रहीं हैं। इसी के मद्देनजर औद्योगिकीकरण को रोजगार देने वाला सेक्टर समझा गया और उद्योगों को कुशल हाथ उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सैडमेप जैसे संस्थान की आधार शिला रखी। माना गया कि सैडमेप से रोजगारों के बारे में जानकारियां पाकर युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और वे समाज की उत्पादकता बढ़ाने में सहयोगी साबित होंगे।

औद्योगिकीकरण के लिए मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया। कहा गया कि जब उद्योग आएंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। इस बीच सरकार ने उद्योगों की जरूरतें पूरी करने के लिए कौशल उन्नयन विभाग भी बना डाला। हालांकि उद्योग विभाग के साथ कदमताल करते हुए बरसों से सैडमेप अपने कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहा है इसके बावजूद सरकार को आईटीआई के साथ कदमताल करने वाले ढांचे की जरूरत महसूस हुई थी।

इस संस्थान का ढांचा खड़ा करने में स्व. पीएन मिश्र जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके बाद संस्थान की बागडोर संभालने वाले जितेन्द्र तिवारी ने संस्थान को बैलेन्स शीट पर मुनाफा कमाने वाला संस्थान बनाने में ही रुचि दिखाई।

दरअसल उनकी नौकरी पिछले दरवाजे से आरंभ हुई थी। इसके पहले तक वे एमपीएफसी में तैनात देश के कुख्यात अफसर विश्वपति त्रिवेदी के कमीशन एजेंट हुआ करते थे। बाद में उन्हें विवादित दस्तावेजों के आधार पर सैडमैप में नौकरी दिला दी गई। तबसे सैडमैप में औद्योगिक विकास के मद्देजनर चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम धीरे धीरे बंद कर दिए गए और सरकारी संस्थानों से बजट खींचने वाले कार्यक्रम चलाए जाने लगे।

खुद को आला अफसर दिखाने के लिए श्री तिवारी ने अपने लैटरहैड और विजिटिंग कार्ड पर त्रिमूर्ति का चिन्ह छपवा दिया जिसे लेकर शिकायतें हुई और बाद में जांच के बाद उन्हें कथित तौर पर माफी भी मिल गई।

राज्य सरकार का तकनीकी शिक्षा विभाग जब उद्योगों के लिए कौशल उन्नयन के पाठ्यक्रम चला रहा है तब सैडमैप को इस माहौल के साथ कदमताल करना था। सरकार की नीतियों से उलटा चलकर सैडमैप केवल अपनी कमाई बढाने के लिए उत्पादकता के बजाए सेवा क्षेत्र पर केन्द्रित होकर रह गया है। इस उलटबांसी के बीच कर्मचारियों को प्रताडित किया जा रहा है,उन्होंने शिकायतें भी की हैं लेकिन भाजपा सरकार मौन है।

राजनीतिक तिलिस्मों पर फतह का महायज्ञ
जासूस बादशाह
भोपाल, मंगलवार 14 मई 2013

खबरों की बंदूक से सत्ता का संधान

सत्ता संधान का बहुत चर्चित वाक्य है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। समय के साथ वह जुमला पूरी तरह बदल गया है। सत्ता अब मीडिया के गलियारों से होकर ही गुजरती है। इसीलिए हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। देश की दोनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस और भाजपा ने मीडिया का भरोसा जीतने के लिए चैनलों और अखबारों की फौज मैदान में उतार दी है। अन्य राजनीतिक दल भी पीछे नहीं हैं। पुराने मीडिया संस्थानों ने सत्ता संधान के इस मिशन से हटकर अपना काम केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया है। इसीलिए समय समय पर पेड न्यूज की खबरें सुनाई पड़ती रहती हैं। इससे इतर मीडिया के क्षेत्र से जुड़े बहुतेरे पत्रकार आज भी मीडिया को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम समझते हैं। वे केवल इसी विधा के खिलाड़ी हैं। उनके उर्वर दिमाग में हर पल नए नए राजनीतिक दांव पेंच करवटें लेते रहते हैं। उनकी राजनीतिक रिपोर्टिंग हरदम राजनेताओं की सुबह और शाम के करीब होती है। मुक्त बाजार व्यवस्था लागू होने के कुछ सालों बाद तक भी अखबार प्रबंधन बेहतर खबरें और विश्लेषण लिखने वाले पत्रकारों को नौकरी देने में रुचि लेते थे। क्योंकि अखबारों के जनाधार की कड़ी ही बेहतर खबरें होती हैं। जैसे जैसे खबरें बिकने लगीं और डिमांड के आधार पर लिखी जाने लगीं तबसे अच्छे पत्रकारों को विज्ञापन एजेंसियों ने बुक करना प्रारंभ कर दिया। उधर जब अखबारों को बेहतर खबरें और विश्लेषण मिलने लगे और वे खबरें उनकी आय की स्रोत भी बन गईं तो अखबारों ने मूर्धन्य पत्रकारों को विदा करना प्रारंभ कर दिया। अब उनकी रुचि खबरें बटोरने वाले पत्रकारों तक ही सीमित होकर रह गई। इसके लिए देश के बड़े बड़े अखबारों ने पत्रकारों के स्थान पर मैनेजमेंट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को नौकरी देना प्रारंभ कर दिया। इससे जहां उन्हें दिग्गज पत्रकारों की मंहगी तनख्वाहों से निजात मिल गई वहीं उस तनख्वाह में कई पत्रकार उपलब्ध होने लगे। जिन अखबारों ने पत्रकारों के रूप में लड़कियों को नौकरी पर रखा तो उन्हें लड़कियों से प्रभावित होने वाले उद्योगपति और अफसरों का मूक समर्थन भी मिलने लगा। पहले कभी समाचार पत्रों में ब्राह्मणों को नौकरी देने की प्रथा रही है। तब समाज के बीच ब्राह्मणों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था लेकिन जबसे जातिगत सुधारों ने आगे बढ़ने के अवसर खोल दिये हैं तबसे ब्राह्मणों का एकाधिकार छिन सा गया है। बाजार वाद के बीच अब वो पत्रकार सफल हैं जो संस्थान को ज्यादा आय करवाते हैं। वास्तव में समाचार सेवाएं अब अघोषित तौर पर उद्योग का रूप ले चुकी हैं। यही कारण है कि चुनावों की आहट मिलते ही मीडिया संस्थानों ने राजनीतिक दलों से पैकेज पाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। उधर राजनीतिक दलों ने भी खुले हाथों से मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को इनाम बांटना जारी रखा है। जो जहां सत्ता में है वह सत्ता के संसाधनों सुविधाओं से पत्रकारों को अपने पक्ष में करना चाहता है। जिस राजनीतिक दल का चुनावी बजट ज्यादा है खबरें उसके नेताओं को हीरो बना रहीं हैं। इसके विपरीत थैली न खोलने वाले नेताओं को खलनायक बनाया जा रहा है। सूचना के हथियार से थैलीशाहों को बटोरा जा रहा है और योग्य लेकिन फक्कड़ नेताओं को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। कई राजनीतिक दल तो केवल इसलिए जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे संवाद की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए मीडिया का ये दुरुपयोग अच्छे संकेत नहीं देता है। पत्रकारों को बेहतर संसाधन मिलने चाहिए ताकि वे लोकतंत्र की सही तस्वीर उभार सकें। जो लोग मीडिया को केवल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहे हैं उन पर अंकुश भी लगाया जाना जरूरी है।

दरवाजे पर दीदी की दस्तक

– वीरेन्द्र जैन –

उमा भारती पिछले कुछ दिनों से` वात्सल्य भाव से म.प्र. के चक्कर अधिक लगा रही हैं। जिन शिवराज सिंह चौहान पर बड़ामल्हरा चुनाव के दौरान उन्होंने उनकी हत्या करवाने के प्रयास का आरोप लगाया था, अब वे उनके बड़े भाई का पद पाने लगे हैं। समानांतर रूप से उनके पैनल के लोग विधानसभा चुनावों में टिकिट पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और चुनावी तैय्यारियों में जुट चुके हैं, जो टिकिट न मिलने की दशा में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।

बाबरी मस्जिद ध्वंस के मुख्य आरोपियों में सम्मलित होने के बाद से उमा भारती ने निरंतर इतने संघर्ष किये कि मीडिया वाले उन्हें साध्वी से फायर ब्रांड लीडर तक कहने लगे। उनके इसी जुझारू तेवर के कारण उनकी पार्टी द्वारा उन्हें उन चुनाव क्षेत्रों में झौंका जाता रहा जहाँ भाजपा को जीतने की सम्भावना बिल्कुल नहीं होती थी। अपनी ज़िद पर भोपाल से टिकिट लेने के पहले वाले चुनाव में उन्हें खजुराहो से लड़ाया गया था, जहाँ कांग्रेस की आपसी फूट के कारण सौभाग्यवश वे जीत तो गयीं पर अपनी असली हैसियत को समझ गयी थीं, तब दूसरी बार उन्होंने खजुराहो क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में स्वास्थ ठीक नहीं रहने के बहाने भोपाल जैसे सुरक्षित क्षेत्र से टिकिट लेना ठीक समझा था। जिसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश भाजपा के भीष्म पितामह सुन्दरलाल पटवा समेत बहुत सारे लोगों से टकराना पड़ा था। इस टकराहट में उनकी नुकसान पहुँचाने की क्षमता ने बड़ा काम किया था और उन्हें मजबूरन टिकिट देना पड़ा था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनने के लिए उन्हें टकराना पड़ा था, जहाँ से केन्द्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें भोपाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आन्दोलन करने के लिए तैनात किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं की पूरी फौज थी। इस दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने अनशन स्थल पर अपनी हत्या की सम्भावनाएं व्यक्त कीं पर दिग्विजय सिंह द्वारा मेडिकल कराये जाने के प्रस्ताव के बाद वे अनशन से अचानक उठ कर केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से स्तीफा दे अज्ञातवास पर चली गयीं। उनके अज्ञातवास से लौटने के बाद एक अखबार ने उनके बारे में कुछ ऐसा छाप दिया जिसको अपमानजनक मानकर वे उस अखबार के खिलाफ अनशन पर बैठ गईं।

अटलजी द्वारा उन्हें फिर से मंत्रिमण्डल में सम्मलित किये जाने के कुछ ही दिन बाद उन से मंत्रिपद ले मध्यप्रदेश के विधान सभा चुनाव में इस समझ के साथ भेजा गया कि वहाँ दिग्विजय सिंह जैसे चतुर राजनीतिज्ञ के सामने जीतना तो असम्भव है पर उमाजी की साम्प्रदायिक छवि से चुनाव में ध्रुवीकरण तेज होगा और भविष्य में मदद मिलेगी। पर यहाँ भी सरकारी कर्मचारियों के असंतोष व कांग्रेस की गुटबाजी से ऐसे पाँसे पड़े कि वे पार्टी को विधानसभा चुनाव जिता ले गयीं और चुनाव परिणामों से हतप्रभ भाजपा नेतृत्व को वादे के मुताबिक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। भाजपा ने उन्हें संगठन के अनुशासन में कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना चाहा तो यहाँ पर भी उन्हें असली भूमिका पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। एक बार तो उन्होंने कहा कि जिसे संगठन का काम मिला है वह संगठन का काम करे और जिसे सरकार चलाने का काम मिला है वह सरकार चलायेगा। अचानक संगठन से सलाह लिए बिना उन्होंने अपने विश्वसनीय लोगों को निगम मण्डलों के पद बाँटे और चुपचाप तीर्थयात्रा पर निकल गयीं। लौट कर आने पर उन्होंने संगठन के लोगों से खूब टकराहट ली तो संगठन ने उन्हें पद से हटाने की कमर कस ली। संयोग से उसी समय हुबली काण्ड का फैसला आ गया जिसमें वे दोषी सिद्ध हुयीं। अवसर की तलाश में बैठे भाजपा नेतृत्व ने उनके साथ सहानिभूति दिखाने की जगह जिस त्वरित गति से उन्हें पद से हटने के आदेश दिये वैसी तेजी न पहले कभी दिखायी थी और न ही बाद में दिखायी।

वैकल्पिक मुख्यमंत्री पद सम्हालने के लिए अरुण जैटली के साथ जिन शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से भेजा गया था, उनको सत्ता देने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया और अपने अनुशासन में रहने के प्रति आश्वस्त बाबूलाल गौर को सत्ता सौंपी। अपमानित जैटली और शिवराज वापिस लौट गये। इस टकराहट का लाभ लेने के लिए कर्नाटक की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हुबली के उस प्रकरण को जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी, राजनीतिक आन्दोलन मानकर वापिस ले लिया जिससे उमाजी जेल से बाहर आ गयीं। पर भाजपा ने वादे के बाद भी इतनी जल्दी मुख्यमंत्री फिर से बदलने से मना कर दिया और एक साल इंतजार करने को कहा। एक साल तक बाबूलाल गौर के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहने के बाद भी जब उन्हें सत्ता नहीं मिली तो वे बिफर गयीं। अरुण जैटली द्वारा उनकी आत्महत्या कर लेने की धमकी को प्रैस को लीक करने की सूचना से वे और भी व्यथित हुयीं तथा टीवी कैमरों के सामने अडवाणी समेत राष्ट्रीय नेतृत्व को भला-बुरा कह डाला जिस कारण वश उन्हें निलम्बित करना पड़ा था। विधायकों के बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री चयन की उनकी माँग को ठुकराते हुए 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह से पराजित रहे शिवराज सिंह चौहान को बतौर मुख्यमंत्री बैठा दिया।आक्रोश में उन्होंने पार्टी छोड़ी, तिरंगायात्रा, रामरोटी यात्रा, आदि निकालीं, नई पार्टी बनायी उससे विधानसभा चुनाव लड़े, अपनी पार्टी के पक्ष में बारह लाख तक वोट पाये, पाँच विधायक जिताये, पर भावी सम्भावनाएं सूंघ कर, पार्टी समेट कर भाजपा में पुनर्प्रवेश के लिए लाइन में लग गयीं। उनसे लम्बी प्रतीक्षा करवायी गयी, इस बीच स्वार्थ के कारण जुड़े सारे लोग एक एक करके उनका साथ छोड़ते गये और उनसे अपमानित हो चुके लोग उनके पुनर्प्रवेश में बाधक बन कर अड़ गये। गडकरी और संघ दोनों के साथ उन्होंने ढेर सारी बैठकें की और आखिरकार उन्हें मना ही लिया। संघ के आदेश के सामने शिवराज सिंह की स्तीफे की धमकी काम नहीं आयी, पर मध्यप्रदेश में उमाजी के प्रवेश करने पर पाबन्दी लगवाने में वे सफल रहे। अपने पिता समान भाई की गम्भीर बीमारी की दशा में उन्हें देखने आने के लिए भी अपने प्रदेश में उन्हें गुपचुप आना पड़ता था। इसी बीच गोबिन्दाचार्य जैसे गुरुसम सलाहकार ने भी उनसे दूरी बना ली।

उन्हें म.प्र. से दूर रखने और अन्यत्र व्यस्त रखने के लिए उन्हें गंगा की स्वच्छता का गैर राजनीतिक प्रभार सौंप दिया गया और बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश के एक लोधी बहुल चुनाव क्षेत्र से टिकिट दे दिया गया, इतना ही नहीं चुनाव के दौरान, सरकार बनने की दशा में उन्हें उ.प्र. का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गयी क्योंकि चुनाव परिणामों का सही अनुमान सबको था इसलिए इस घोषणा में भाजपा को कोई खतरा नहीं था। वे किसी तरह खुद तो चुनाव जीत गयीं पर भाजपा के वोट प्रतिशत में ही गिरावट नहीं आयी अपितु उसकी सीटें पिछले चुनाव से भी दो कम हो गयीं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो घोषित कर दिया गया था पर उन्हें विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया तो वे भी शपथ लेने के बाद विधानसभा नहीं गयीं। भाजपा के नेतृत्व समेत मध्यप्रदेश के नेता खुश थे कि उन्होंने उमाजी का प्रदेश निकाला ही कर दिया। उल्लेखनीय है कि उमाजी ने म.प्र. की भाजपा सरकार को अपना बच्चा बताया था और शिकायत की थी कि उन से उनका बच्चा छीन लिया गया है।

पिछले दिनों लोधी जाति के नेता कल्याण सिंह ने लखनऊ में आयोजित एक समारोह में अपनी पार्टी का समर्पण भाजपा में करा दिया पर उस कार्यक्रम में उ.प्र. से विधायक व मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित प्रत्याशी रही उमाभारती को कोई स्थान नहीं दिया गया। दोनों ही नेता लोधी जाति के नेता हैं और दोनों ने ही भाजपा में मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनायी थी पर उसके असफल होने के कारण एक एक करके भाजपा में वापिस आते गये हैं। कल्याण सिंह नहीं चाहते हैं कि उमा भारती उत्तरप्रदेश में लोधियों की नेता के रूप में उभरें इसलिए वे उन्हें उसी तरह दूर करना चाहते हैं, जैसे कि मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उन्हें प्रदेश में घुसने ही नहीं देना चाहते। स्मरणीय है कि जब उमा भारती ने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था तब महीनों तक उनके पाँच विधायकों को विधायक दल में सम्मलित नहीं किया गया था व उन्हें मंत्री तो दूर किसी को भी निगम मण्डल के अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया है। उमा भारती से जुड़े रहे लोगों को संगठन में भी उचित स्थान नहीं मिला है व किसी

(शेष भाग पेज सात पर पढ़िए)

नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को केवल एक शपथ पत्र देना होगा

निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

भोपाल ।मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नामांकन-पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को अब दो के स्थान पर सिर्फ एक शपथ-पत्र ही लगाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र के प्रारूप (फार्म-26) में संशोधन किया है।

उम्मीदवारों को इसके पूर्व फार्म-26 में दो शपथ-पत्र देना पड़ते थे। एक शपथ-पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि तथा दूसरी में देनदारी, सम्पत्ति विवरण और शैक्षणिक योग्यता बताना पड़ती थी। निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने दोनों शपथ-पत्र को एक में शामिल करने के लिये संशोधन किया है। दोनों शपथ-पत्र की जानकारी अब एक ही प्रारूप में रहेगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने फार्म-26 का संशोधित प्रारूप विगत एक अगस्त, 2012 को राजपत्र में अधिसूचना के जरिये प्रकाशित किया है।

पुनरीक्षित फार्म-26 में अब एक ही शपथ-पत्र देना होगा। निर्वाचन आयोग ने शपथ-पत्र के पुनरीक्षित प्रारूप को सभी निर्वाचन अधिकारियों की जानकारी में लाने के निर्देश दिये हैं। शपथ-पत्र की नई व्यवस्था विधानसभा चुनाव के साथ ही लोक सभा निर्वाचन में भी लागू रहेगी।

रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र के पुनरीक्षित प्रारूप में क्रमांक एक से 6 तक उम्मीदवार के विवरण के अलावा पेन नम्बर, आयकर विवरणी, न्यायालय में लम्बित मामले और उनका पूर्ण विवरण, किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराये या नहीं ठहराये जाने के दंडादेश की स्थिति आदि की विस्तृत जानकारी रहेगी। शपथ-पत्र के इसी हिस्से में बिन्दु क्रमांक 7 से 9 तक उम्मीदवार स्वयं या उसकी पत्नी तथा सभी आश्रितों की अस्तियों (जंगम और स्थावर) का विस्तृत ब्यौरा, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों का ब्यौरा तथा वृत्ति या उपजीविका का विवरण दिया जायेगा। इसी शपथ-पत्र के क्रमांक 10 में अभ्यर्थी की शैक्षणिक अहर्ता का विवरण रहेगा।

शपथ-पत्र के भाग-ख में जो जानकारी देना होगी उसमें अभ्यर्थी का पूरा नाम, डाक का पता, उस राजनैतिक दल का नाम जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया है, लम्बित ऐसे मामलों की संख्या जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं। ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनके न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है। ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया, एक या उससे अधिक वर्ष के लिये कारावास से और दंडित किया गया है।

इसी भाग में अभ्यर्थी की स्थायी लेखा संख्या, अंतिम आयकर विवरणी, कुल दर्शित आय, अस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में), जंगम अस्तियाँ, स्थावर अस्तियाँ, स्वर्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत, क्रय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/संनिर्माण लागत, सम्पत्ति की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत, सरकारी शोध्य, बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से लिया गया ऋण, उच्चतम शैक्षिक अहर्ता आदि की जानकारी का समावेश रहेगा। शपथ-पत्र के अंतिम हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

उम्मीदवार को शपथ-पत्र नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपरान्ह 3 बजे तक जमा करना होगा। शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जाना चाहिये। शपथ-पत्र में उल्लेखित सभी स्तंभों को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा। कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जायेगा, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' का उल्लेख करना होगा। शपथ-पत्र टंकित अथवा सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखा होना चाहिये।

भोपाल की महापौर सुश्री कृष्णा गौर ने नगरीय प्रशासन मंत्री साथ तालाब के विकास के लिए नौकाविहार किया।

42 जिलों में भूमि नक्शों का डिजिटाईजेशन एवं खसरा-नक्शा लिंकिंग कार्य पूर्ण

भोपाल राज्य शासन द्वारा नेशनल लेण्ड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सभी जिलों में भूमि नक्शों का डिजिटाइजेशन और खसरा/नक्शा लिंकिंग कार्य किया जा रहा है। अप्रैल, 2008 से प्रारंभ इस योजना के तहत 42 जिलों में भूमि नक्शा डिजिटाइजेशन और नक्शा लिंकिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें से 33 जिलों के लिंक्ड खसरा-नक्शा वेब पर भी होस्ट हो चुके हैं। शेष 8 जिलों- गुना, अशोकनगर, देवास, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, पन्ना और दमोह में यह कार्य प्रगति पर है।

राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि कम्प्यूटराइज्ड खसरा एवं डिजिटाईज्ड नक्शे को एक-दूसरे से लिंक करने, खसरा में हुए बटांकनों के अनुरूप डिजिटाइज्ड नक्शे के डिजिटल डाटा को अद्यतन करने और ए-4 साइज पर नक्शा एवं खसरा का प्रिंट उपलब्ध करवाने के लिये एनआईसी द्वारा भू-नक्शा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण सभी जिलों में जूनियर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षित पटवारियों को प्रदान कर दिया गया है ।लिंकिंग से पूर्ण जिले जिनके नक्शे वेब पर हैं। वे हैं श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, डिण्डोरी, रीवा, सीधी और सतना। पाँच कम्पनियाँ भूमि नक्शा डिजिटाईजेशन का कार्य कर रही हैं।

मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु-दर में उल्लेखनीय गिरावट

भोपाल । मध्यप्रदेश में मातृत्व सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप मातृ मृत्यु-दर में उल्लेखनीय गिरावट आयी है। विगत 6 मई को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे बुलेटिन 2011-12 के अनुसार मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु-दर में एक वर्ष में 33 पाइंट और विगत 10 वर्ष की तुलना में 102 पाइंट की गिरावट आयी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, 2013 को शुरू किये गये ममता अभियान में मातृ मृत्यु-दर को वर्ष 2013-14 में और घटाकर 200 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2001-03 में मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु-दर 379 प्रति लाख जीवित जन्म थी, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 277 हो गयी है। वर्ष 2010-11 के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु-दर 310 थी, जो वर्ष 2011-12 में 33 पाइंट गिर गयी।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में मातृ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये गये हैं। संस्थागत प्रसव को प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया गया है। प्रदेश में 10 साल पहले 26 प्रतिशत संस्थागत प्रसव होते थे, जो अब बढ़कर 81 प्रतिशत से अधिक हो गये हैं। प्रदेश में 24×7 प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सीमॉक और बीमॉक को क्रियाशील किया जा रहा है। इसके लिये मानव संसाधन की पूर्ति, अधोसंरचना विकास, नि:शुल्क औषधि और सामग्री, जाँचें, रेफरल परिवहन और भोजन की व्यवस्था शासकीय संस्थाओं में की जा रही है।

प्राचीन खेल विधा मलखम्ब को मिला राज्य खेल का सम्मान

भोपाल । भारत की अति प्राचीन खेल विधा मलखम्ब को मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य खेल घोषित कर दिया है। इस संबंध में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। यह सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में भी प्रकाशित हो गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मार्च माह में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। प्रदेश में 14 मलखम्ब केन्द्र इंदौर, खरगोन, उज्जैन, बैतूल, दतिया, पन्ना, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, जबलपुर, छतरपुर एवं सागर में संचालित हैं। मलखम्ब भारत का एक पारम्परिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक खम्बे या रस्सी के ऊपर तरह-तरह के करतब दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्पर्धा में इसके तीन प्रकार प्रचलित हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव-द्वितीय के गुरु श्री बालम भट्ट दादा देवधर ने इस विधा को एक नई पहचान दी। सन् 1958 में पहली बार नेशनल जिमनास्टिक चेम्पियनशिप के तहत मलखम्ब को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया।

फिक्स्ड (स्थायी) मलखम्ब में जमीन पर स्थापित सागोन या शीशम की 10 से 12 फीट ऊँची तथा नीचे से 5 से 6 इंच और ऊपर से 1.5 से 2 इंच व्यास की लकड़ी पर करतब दिखाया जाता है।

हेंगिंग मलखम्ब

यह फिक्स्ड मलखम्ब का छोटा संस्करण कहा जाता है। इसमें आमतौर पर संतुलन अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के पोल पर एक हुक तथा चेन की मदद से जमीन से 3.5 से 4 फीट की ऊँचाई पर एक दूसरी लकड़ी को लटकाया जाता है तथा उस पर खिलाड़ियों द्वारा मलखम्ब किया जाता है।

शेप मलखम्ब

प्रमुख रूप से महिला खिलाड़ियों के लिये प्रयुक्त यह मलखम्ब का एक आधुनिक प्रकार है। इसमें रस्सी के सहयोग से विभिन्न योगिक मुद्राओं को दर्शाया जाता है।

दिल

द मामला है......

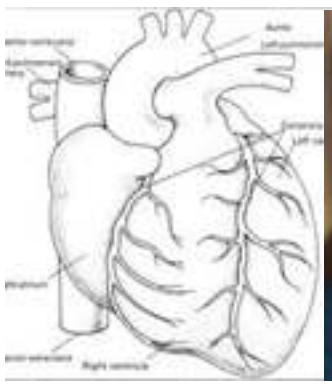

डॉ. रश्मि मलैया, सहायक प्राध्यापक गृहविज्ञान, शास. स्व.त्ना.कन्या उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर

आधुनिक जीवन शैली और हृदय रोग

भारतीय समाज की जीवन शैली में बीते कुछ सालों में काफी तेजी से बदलाव आए हैं। जिनके परिणाम स्वरूप हृदय रोगों में भी इजाफा हुआ है। जीवन शैली में बदलाव आने के कई कारण हैं। जिनमें आर्थिक संपन्नता और आधुनिकीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। आज की आबादी में युवाओं की संख्या अधिक है। जिनके रहन सहन और काम करने की शैली पहले से काफी बदल गई है। आर्थिक विकास में तेजी होने के कारण लोगों को वेतन पहले से काफी ज्यादा मिलने लगा है। अधिकांश आई.टी. उद्योगों में तो रात की पालियों में काम होता है। जिससे नींद के स्वाभाविक पैटर्न में भी बदलाव आया है। इसी तरह फास्ट फूड और ड्रिंग्स खानपान का हिस्सा बन गए हैं। घरों में पकाए गए खाने का चलन धीमा होता जा रहा है। रेस्टोरेंट या फास्ट फूड पर निर्भरता बढ़ रही है। धन की अधिकता ने शराब खोरी और धूम्रपान को बढ़ावा दिया है। इसकी वजह से आ रहीं बीमारियां दिल के दौरे का जोखिम बढ़ा रहीं हैं। आज मोटापा,मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, चयापचय में विकृति जैसी बीमारियों में बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय 5 करोड़ हृदय रोगी हैं।

भारतीय उप महाद्वीप के निवासियों को दिल की बीमारियों का प्रकोप दूसरी नस्ल के लोगों की तुलना में अधिक होता है। यह समस्या हमें विरासत में यानि अनुवांशिक तौर पर मिली है। जब हम इतने हाईरिस्क फेक्टर के साथ जी रहे हैं तो क्यों न हम अपनी जीवनशैली में थोड़ा बदलाव लाएं और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहने की कोशिश करें। हम भारतीयों में हृदय की बीमारी यानि दिल का दौरा ज्यादा ही नहीं बल्कि अब कम उम्र के लोगों में भी ज्यादा पाया जा रहा है। कुछ सालों पहले तक दिल का दौरा आमतौर पर 65 साल की उम्र की बीमारी माना जाता था। पर अब ये बीमारी 35 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखी जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो ये है कि पहले घंटे में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। जिसका सीधा असर लोगों के परिवारों और समाज पर पड़ रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2007में भारत के भविष्य के लिए एक चेतावनी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2020 में 70 लाख भारतीयों की मौत जीवनशैली आधारित बीमारियों के कारण होगी। आज मध्यवय के लगभग 50 प्रतिशत लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। देश में प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति को किसी रूप में क्रोनिक किडनी की बीमारी होने की आशंका है। प्रतिवर्ष करीब 1,50, 000 लोग गुर्दे फेल होने की अंतिम अवस्था के साथ मरीज बनकर आ रहे हैं।

दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज यानि हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो 2010 में हमारा देश दिल के रोगों की विश्व राजधानी बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार 2015 तक दिल के रोगों से मरने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यानि वर्तमान दर में 100 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि अन्य देशों में दिल के रोगों से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए जापान व फिनलैंड में 60 प्रतिशत , आस्ट्रेलिया, कनाडा, व अमेरिका में 50 प्रतिशत व पश्चिमी यूरोप में 25 प्रतिशत की कमी आई है।

भारत में हृदय रोग एवं हृदय की धमनियों के रोगों के लिए जिम्मेदार कारण हैं, तीव्र शहरीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या एवं खानपान में परिवर्तन, 1960 के बाद से सीएडी की दर में बढ़ोत्तरी हुई है। जब यह 1 प्रतिशत थी। 2003 में यह दर 11प्रतिशत और 2008 में 14 प्रतिशत थी।

हृदय रोग के प्रमुख कारण– धूम्रपान एवं ब्लडप्रेशर, डायबिटीज एवं मोटापा, वंशानुगत रोग एवं खानपान, शारीरिक काम कम करना, कोलेस्ट्रॉल लेबल बढ़ना, आदि हृदय से संबंधित प्रमुख जांचें, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए चालीस साल की उम्र के बाद नियमित रूप से दिल के स्वास्थ्य संबंधी जांचे कराना चाहिए। जैसे ईसीजी, टीएमटी, इको कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, थैलियम स्ट्रेस टैस्ट, आवश्यकतानुसार और डाक्टरी सलाह के मुताबिक करवा लेना चाहिए।

हृदय रोग चिकित्सा के नए आयाम– आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के शोध इंसान की सेहत को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के नित नए शोध दिल की बीमारियों से निपटने के नए रास्ते भी खोज रहे हैं। हृदय रोगों की आधुनिक चिकित्सा अब अधिक सुरक्षित नतीजे देती है।

बायो एब्जोर्बेविल स्टेट्स ङ्क ये स्टेटस अपना काम बखूबी निभाकर घुल जाएंगे. इससे दोहरी एंटी प्लेटलेट, थैरेपी की आवश्यकता नहीं रहेगी।

ड्रग एल्यूटिंग बैलून– यानि औषधि छोड़ने वाली जाली। यह इस तरह डिजाईन की गई है कि ब्लाकेज पर लगाने के बाद यह अर्से तक औषधि छोड़ती रहती है।

लो कास्ट स्टेंट्स– इनकी ट्रायल अभी जानवरों पर चल रही है। फिलहाल ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स एक लाख 25 हजार रुपए तक मिलते हैं। लो कास्ट स्टेंट्स की लागत 40 हजार रुपए तक आ सकती है। इनके आने के बाद देश में हृदय रोग की चिकित्सा का परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है।

दिल के इलाज के कुछ घरेलू नुस्खे–

1. कोलेस्ट्राल का स्तर ठीक रखने के लिए दस ग्राम पुदीने का काढ़ा बनाएं और रोजाना खाली पेट सुबह गर्म गर्म पिएं।
2. कोलेस्ट्राल नियंत्रण के लिए 3 ग्राम हल्दी पाऊडर को गर्म दूध के साथ लें।
3. लहसुन की दो फांक सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ लें।
4. सेब और अनार का जूस तथा आंवले का मुरब्बा दिल को ताकत देता है।
5. अर्जुन के पेड़ की छाल का 5 ग्राम चूर्ण खाली पेट लें।

हृदय को बल देने वाले हितकारी भोजन–हृदय रोग और भोजन का आपसी संबंध किसी से छिपा नहीं है। अत: अपने हृदय को स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ भोजन संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें। इन्हें अपनाकर आप अपने हृदय को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं।

1. भोजन में वसा का प्रयोग यथासंभव कम से कम करें।
2. एल्कोहल वाले पेयों का सेवन भी बहुत कम मात्रा में करें।
3. मैदा चीनी , सूजी से बने पदार्थों का सेवन भी बहुत कम मात्रा में करें।
4. पनीर , चीज, मक्खन, और घी हृदय के लिए घातक हैं।
5. पाम आयल व नारियल के तेल का अधिक प्रयोग न करें।
6. स्किम्ड दूध की लस्सी, शर्बत व वसारहित दूध का दही लेना बेहतर है। आईस्क्रीम का सेवन हृदय के लिए घातक है।
7. अपने भोजन में रेशेदार पदार्थों की मात्रा बढाएँ।
8. यदि मांसा हारी हैं तो अंडे का सफेद भाग ही खाएं।
9. वनस्पति घी का प्रयोग भूलकर भी न करें।
10. अलसी का सेवन करें। क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फेटी एसिड होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे मस्तिष्क स्नायुतंत्र, व आंखों के विकास व उनके सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मन को प्रसन्न रखते हैं। क्रोध से मुक्ति, स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के अलावा मोटापे को घटाने में भी ओमेगा 3 फेटी एसिड महत्वपूर्ण सहयोगी होते हैं। इनमें मौजूद फायबर डायबिटीज और मोटापे पर चमत्कारिक असर दिखाते हैं। इसमें एंटी आक्सिडेंट लिंगनेन, लाईकोपोन, ल्यूटिन और जियाजेंथिन पाया जाता है, जो हृदय रोगों में बड़ा ही हितकारी है।

कोलेस्ट्राल प्रबंधन– हृदय रोग होने की आशंका रक्त में कोलेस्ट्राल के स्तर से जुड़ी होती है। रक्त में एल डी एल कोलेस्ट्राल का स्तर जितना अधिक होता है हृदय रोग या हृदयाघात होने का जोखिम उतना ही बढ़ जाता है।

1. कोलेस्टॉल का स्तर काबू में रखने के लिए उपचारात्मक जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए।
2. टीएलसी आहार–यह कम वसा वाली कम कोलेस्ट्राल वाली आहार योजना है। जिसमें प्रतिदिन संतृप्त वसा से 7 प्रतिशत से कम कैलोरी और 200 मिलीग्राम से कम आहार प्रदत्त कोलेस्ट्राल प्राप्त होता है।
3. वजन का प्रबंधन।
4. शारीरिक गतिविधियों को अपनाकर आप ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

आधुनिक जीवन की आपाधापी से उपजे इस रोग का निदान करने में जुटे आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि यदि स्वस्थ लोग भी नियमित तौर पर लौकी का जूस पीते हैं। आंवला और एलोवेरा का जूस पीते हैं तो वे बड़ी हद तक हृदय रोग से बच सकते हैं। लौकी का जूस उन्हें रक्त की अम्लता से बचाता है। इस रस के प्रभाव से धीरे धीरे हृदय रोगियों की धमनियां खुल जाती हैं और उन्हें आपरेशन की टेबल तक नहीं जाना पड़ता है। पतंजलि योग संस्थान मरीजों को नियमित प्राणायाम करने की सलाह देता है। जाहिर है कि यदि आप अभी स्वस्थ हैं तो अपनी जीवन शैली, आहार व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाने की पहल करें और यदि बीमार हैं तो ये पहल कुछ ज्यादा ही तेज करें।

हृदय रोग आधुनिक हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैलती बीमारी बन गई है। गलत खानपान और उनींदे रहनसहन ने देश के युवाओं को बीमार कर दिया है। टीवी सीरियलों में दिखाई जा रहीं कामोद्दीपक कहानियों ने युवाओं को दिल से लाचार बना दिया है। डाक्टर हैरान हैं और सरकारें परेशान,बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में पैर रगड़ रहे हैं। उपभोक्तावाद की दौड़ में शामिल युवा रात दिन काम करने को मजबूर हैं। वे अपनी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। डाक्टर बता रहे हैं कि उन्होंने हृदय की धड़कनें कायम रखने के लिए नए उपकरण विकसित किए हैं पर जब हृदय धड़केगा तभी तो ये उपकरण भी कामयाब होंगे। इसी समस्या से सावधान करने के लिए गृहविज्ञान की प्राध्यापिका डॉ.रश्मि मलैया ने इस कठिन रोग की ओर आपका ध्यान खींचा है।

दस हाथी के दम वाली बूटी

आचार्य हुकुमचंद शनकुशल कहते हैं कि ये कोई अजूबा नहीं है। वैदिक आयुर्वेद में दी गई विधियों से यदि जड़ीबूटियों का सेवन किया जाए तो 10 हाथियों की शक्ति कहे जाने वाले मानव बल को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जड़ी बूटियों के ये दिव्य प्रयोग आयुर्वेद में सदियों पहले खोज लिए गए थे। समय समय पर इन योगों का इस्तेमाल देश के वैद्य और आहार विशेषज्ञ करते रहे हैं। जड़ी बूटियों के साथ आसनों और प्राणायामों से खिलाड़ियों के शरीर में जो ताकत आती है वह किसी भी आधुनिक स्टीराईड से उपजी ताकत से कम नहीं होती है।

खेलों में सफलताएं पाने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी तरह तरह के जतन करते रहते हैं। खिलाड़ियों की शक्ति बढ़ाने के लिए हुनरमंद डाक्टर उन्हें कई तरह के स्टीरॉयड देकर उनकी ताकत बढ़ाते हैं, लेकिन जबसे डोप टैस्ट की नई नई प्रणालियां विकसित हो गई हैं तबसे खिलाड़ियों के लिए अपने बलबूते नए रिकार्ड बनाने की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। अनादिकाल से हिंदुस्तान के अखाड़ों में पहलवानों को मजबूत पट्ठे बनाने की कवायद चलती रही है। इसके बावजूद हिंदुस्तान के पहलवान विश्व मुकाबलों में काफी पिछड़ रहे हैं। एथलेटिक्स, और हाकी जैसे खेलों में कभी झंडे गाड़ने वाला सवा सौ करोड़ लोगों का हिंदुस्तान आज पिछड़े देशों के बीच खड़ा नजर आता है। हिंदुस्तान की इस दशा और दिशा को बदलने का ख्वाब देखने वाले एक जिमनास्ट ने गरीबी से जूझते हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के लिए कुछ सामान्य जड़ी बूटियों का योग तैयार किया है । ये जड़ी बूटियां हर जगह आसानी से मिलती हैं और बड़ी कम लागत में विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की नस्ल तैयार करने में सफल साबित हो रहीं हैं।

महर्षि पतंजलि की जन्म भूमि भोपाल(गोंदरमऊ) में बरसों से ये करिश्मा करने में जुटे प्रकृति प्रेमी आचार्य हुकुमचंद शनकुशल ने अपने प्रयोगों से जो खिलाड़ी तैयार किए हैं वे दुनिया भर के खेलों में अपने झंडे गाड़कर दिखा चुके हैं। आनंद नगर स्थित भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र परिसर कई बार इस तरह के प्रयोगों का साक्षी बन चुका है।

इस परिसर में देश के विभिन्न इलाकों से आने वाले खिलाड़ी कुछ सहज नुस्खों के बलबूते खेलों के विश्व रिकार्ड तोड़ने का करिश्मा दिखा रहे हैं।भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र न केवल खिलाड़ियों बल्कि असाध्य और रहस्यमयी रोगों से पीड़ित मरीजों को भी सहारा दे रहा है।

यौगिक चिकित्सा के इस अनूठे केन्द्र का लाभ मध्यप्रदेश के कई दिग्गज भी उठा चुके हैं। आम नागरिकों को जादुई इंसान बनाने वाला ये केन्द्र अब तक मध्यप्रदेश के लोगों की दीवानगी का ऊर्जा स्रोत भले ही न बन पाया हो लेकिन देश और दुनिया के बहुतेरे विशेषज्ञ इस योग अनुसंधान केन्द्र के पक्के प्रशंसक हैं। वे यहां आते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाकर लौटते हैं। दिन ब दिन भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र की यशोगाथा फैलती जा रही है।

विश्व प्रसिद्ध योग चिकित्सक बाबा रामदेव आज भले ही देश विदेश में यौगिक चिकित्सा के नए आईकन बन गए हों पर आचार्य हुकुमचंद शनकुशल के मार्गदर्शन में चलने वाले अनुसंधानों से जो प्रणाली विकसित हुई है वह बेहद जमीनी और चमत्कारी है। आधुनिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा विधियां, तांत्रिक अनुष्ठानों और आयुर्वेद की बेहद गूढ़ चिकित्सा विधियों के समायोजन से आचार्य हुकुमचंद शनकुशल ने चमत्कारिक फार्मूले खोज निकाले हैं। उन्होंने इन प्रयोगों से अपने शिष्यों को तो सफल बनाया ही है,छोटे छोटे बच्चों को भी हुनरमंद बना दिया है। ये बच्चे यौगिक कलाओं में निपुण हैं और ऊर्जा के भंडार साबित हो रहे हैं। नौ साल के भीमाशंकर शनकुशल ने 1200 मीटर की दूरी 7 मिनिट 52 सैकेण्डो में तेज चाल से पूरी करके विश्व रिकार्ड को तोड़ने की क्षमता हासिल कर ली है।

आचार्य हुकुमचंद शनकुशल कहते हैं कि ये कोई अजूबा नहीं है। वैदिक आयुर्वेद में दी गई विधियों से यदि जड़ीबूटियों का सेवन किया जाए तो 10 हाथियों की शक्ति कहे जाने वाले मानव बल को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जड़ी बूटियों के ये दिव्य प्रयोग आयुर्वेद में सदियों पहले खोज लिए गए थे। समय समय पर इन योगों का इस्तेमाल देश के वैद्य और आहार विशेषज्ञ करते रहे हैं। जड़ी बूटियों के साथ आसनों और प्राणायामों से खिलाड़ियों के शरीर में जो ताकत आती है वह किसी भी आधुनिक स्टीराईड से उपजी ताकत से कम नहीं होती है। उन्होंने बताया कि राजधानी यूथ क्लब के जिन खिलाडियों ने दुनिया भर के लोगों को अचंभित किया है वे विज्ञान के बहुत सहज प्रयोगों से सफलता पाते रहे हैं। आचार्य हुकुमचंद शनकुशल ने खुद अपनी जवानी के दौर में 1972 में सीना फुलाने का विश्व रिकार्ड बनाया था। जब उन्होंने यौगिक क्रियाओं से अपना सीना 32 इंच फुलाकर 48 इंच कर दिया तो लोगों की आंखें फटी रह गईं थीं। सांची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी ने इस करिश्मे से प्रभावित होकर आचार्य हुकुमचंद शनकुशल को आनंद नगर की जमीन इन्हीं कार्यों के लिए प्रदान की थी। बाद में हुकुमचंद शनकुशल की ही एक शिष्या शुभ्रा बोस ने ब्राजील में हुई विश्व तीरंदाजी चैंपियन में अव्वल आकर देश का नाम रोशन किया था। साऊथ अमेरिका के उरुग्वे में हुए आर्टिस्टिक योगा के मुकाबले में भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था।

अनगढ़ मिट्टी से बच्चों को विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाने वाले इस योग विशेषज्ञ का हुनर बहुआयामी है। जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग के लिए तरह तरह की मशीनें बनाकर आचार्य शनकुशल ने अपनी तकनीकी दक्षता के भी उदाहरण पेश किए हैं। रसविद्या के ज्ञान से वे जड़ी बूटियों की चटनियां, अवलेह और आसव अरिष्ट बनाते हैं जो इतने तेज असर करते हैं कि बीमारियां क्षण भर में छूमंतर हो जाती हैं। यज्ञीय चिकित्सा से उन्होंने कई रहस्यमयी बीमारियों का निदान भी करके दिखाया है। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों को डाक्टर तमाम प्रयासों के बाद असाध्य रोगी बता चुके थे।श्री शनकुशल ने उन्हें जड़ी बूटियों की धूनी देकर स्वस्थ बना दिया। जड़ी बूटियों की स्वादिष्ट सब्जियां, हलुए और बाटियां बनाकर वे नकचढ़े रोगियों और बच्चों को भी स्वस्थ कर दिखाते हैं। इस आयुर्वेदिक पाक कला के दीवानों की तादाद बड़ी लंबी है। श्री शनकुशल के एक शिष्य रमन भगत तो कहते हैं कि यदि गुरुजी अपने जड़ी बूटियों के व्यंजनों को बाजार में उतार दें तो स्वाद के दीवाने बड़ी बड़ी होटलों में जाना भूल जाएं। केवल प्राकृतिक जड़ी बूटियों की सुगंधों और स्वाद से श्री शनकुशल ने एसे स्वादिष्ट व्यंजन विकसित किए हैं जो खिलाड़ियों को अपना टारगेट पाने में टैबलैट से ज्यादा कारगर होते हैं।

आचार्य शनकुशल कहते हैं कि उनके इस करिश्मे का आधार केवल आयुर्वेद और यौगिक चिकित्सा ही है। उनका कहना है कि वैदिक ऋचाओं में कई एसे गूढ़ रहस्य छुपे पड़े हैं जिनका आशय आम लोग नहीं समझ पाते हैं। आज आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने वाले चिकित्सक सभी प्रकार के लोगों को कुछ फार्मूलों के आधार पर इलाज देने का प्रयास करते हैं, जबकि आयुर्वेद हर मरीज के लिए नया नुस्खा देता है। हर मरीज की जन्म स्थितियों और शारीरिक प्रकृति के अनुसार जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी बदल जाता है। प्रकृति ने हर व्यक्ति को अद्वितीय बनाया है। हर व्यक्ति की क्षमताएं भी अलग हैं। उसकी बुद्धि भी अलग है और शरीर का तंत्र भी अलग है। एक ही जड़ी बूटी किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है तो उसका ही सेवन दूसरे को बीमार कर सकता है। इसलिए जो लोग केवल जड़ीबूटियों के तत्वों के विष्लेषण के आधार पर इलाज कर रहे हैं वे अपने मरीजों को नए झमेलों की ओर धकेल रहे हैं। इसी प्रकार हर खिलाड़ी के लिए जड़ी बूटियों का नया योग बनाया जाना जरूरी है जो काफी सोच विचार के बाद और लंबे समय के अनुसंधानों के बाद विकसित होता है। इसी योग से खिलाडी की विचार शीलता और उसकी कार्य कुशलता भी विकसित होती है। वास्तव में जड़ी बूटियों का ये प्रयोग बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल बदलाव लाता है। इन प्रयोगों से गुजरने के बाद

बच्चों की जो ट्यूनिंग हो जाती है वह उन्हें बेहतर खिलाड़ी तो बना ही देती है बल्कि वे अपने समकालीन बच्चों से बेहतर, डाक्टर, वैज्ञानिक, वकील, पत्रकार और शिक्षक भी बन जाते हैं। उनका कहना है कि आयुर्वेद को सदियों से जीवन का विज्ञान कहा जाता रहा है। अपने जीवन में तमाम चिकित्सा विधियों का गहरा अध्ययन करने और प्रयोग के बाद ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विधि है। ये न केवल देशी पद्धति है बल्कि ये हमारी संस्कृति से जुडी भी है। देशी जडी बूटियों का इस्तेमाल जैसे हमें रोगमुक्त करता है वैसे ही इनके माध्यम से हम अपने शरीर की क्षमताओं को भी बढ़ा लेते हैं। शरीर की जो कमजोरियां हैं उन्हें हम संतुलित कर सकते हैं।

श्री शनकुशल कहते हैं कि जड़ी बूटियों से शोधित शरीर को जब योग और प्राणायाम से संतुलित किया जाता है तो शरीर की क्षमताओं में चमत्कारिक असर देखने में आता है। शरीर में बढ़ने वाला ये बल पूरी तरह प्राकृतिक होता है और इसका कोई साईड इफेक्ट भी नहीं होता है। जड़ी बूटियां जो बदलाव लाती हैं उनसे मन भी स्वस्थ हो जाता है और तन भी। इसीलिए तो जड़ी बूटियों के इस विज्ञान को व्यापक अनुसंधान की जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद और अन्य वेदों में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। जरूरत है कि उस ज्ञान को आज के संदर्भों में परिभाषित किया जाए। आयुर्वेद के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधानों से ये लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। इसके बाद जब लोगों को आयुर्वेद की आदत पड़ जाए तो कई प्रतिभाशाली लोग इस ज्ञान में नए आयाम भी जोड़ सकते हैं।

आचार्य हुकुमचंद शनकुशल कहते हैं कि प्रकृति ने हमें कई तरह की जड़ी बूटियां दी हैं। ये जड़ी बूटियां हमारे आसपास ही हैं। हम उन्हें पहचानते नहीं हैं और न ही उनकी शक्तियों से परिचित हैं। बाजार में मिलने वाले जंक फूड से सावधान रहने की सलाह देते हुए श्री शनकुशल कहते हैं कि वास्तविक स्वाद जड़ी बूटियों में है। यदि हम स्कूली शिक्षा से आयुर्वेद को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दें तो न केवल जड़ी बूटियों का संरक्षण संवर्धन हो सकेगा बल्कि पर्यावरण बचाने की दिशा में भी हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। उनका कहना है कि जडी बूटियों पर आधारित चिकित्सा विधि हमारे चिकित्सा व्यय को घटा सकती है और लोगों को कुपोषण से भी बचा सकती है। वे कहते हैं कि आज बड़े बड़े अफसर और व्यापारी कुपोषण से ग्रस्त हैं। वे काफी मंहगा भोजन करते हैं पर उनके भोजन में पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। इसके कारण जब वे बीमार होते हैं तो डाक्टरों को उन्हें मंहगी दवाओं का सेवन करवाना पड़ता है जो कई तरह के साईड इफेक्ट के कारण असफल साबित होता है।

वास्तव में देश को यदि हम विश्व पटल पर छलांगे मारता हुआ मुल्क बनाने की हसरत रखते हैं तो हमें घूम फिरकर अपनी सांस्कृतिक विरासत की ही शरण में आना होगा। यही एकमात्र रास्ता है जो हमारे युवाओं को बेहतर खिलाड़ी और बेहतर नागरिक बना सकता है। न केवल हिंदुस्तान बल्कि समूची मानवता को सफल बनाने की दिशा में कार्य कर रहे भारतीय योग अनुसंधान केन्द्र का डंका आज लगभग पैंसठ देशों में बज रहा है इंटरनेशनल योग कंफेडरेशन ने इस आवाज को पूरी दुनिया में बुलंद करने का बीड़ा उठाया है। जरूरत है कि मध्यप्रदेश सरकार भी इसका महत्व समझे और अपने नागरिकों को सफल इंसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। तभी हमारे खिलाड़ी सोना जीतने की दौड़ में अव्वल साबित होंगे।

भाजपा को सबक सीखना होगा

भाजपा के लिए एक सबक यह भी है कि किसी एक नेता पर आश्रित होने की बजाए सामूहिक नेतृत्व को स्थापित करे। नरेन्द्र मोदी हों या कि शिवराज सिंह चैहान - इनके नाम पर हवाई किले बनाने की बजाए मध्यम दर्जे के नेताओं को भी अग्रिम पंक्ति में लाने की कवायद जरूरी है। संगठन को किसी भी कीमत पर सत्ता का अनुचर बनने से अगर भाजपा रोक पाई तभी वह जनता और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरी हो सकती है। भाजपा की सफलता के लिए यह जरूरी है कि वह समन्वय और संवाद को भाषणों और किताबों से परे जमीन पर उतारने की दिशा में प्रयास करे। **अनिल सौमित्र**

कर्नाटक विधानसभा का परिणाम आ चुका है। दलीलें चाहे जो भी हों, सच्चाई सबके सामने है। भाजपा और जनता दल सेकुलर बराबरी पर आ खड़े हुए हैं। राज्य में कांग्रेस को 121, जनता दल (एस) और भाजपा को 40-40 तथा अन्य को 21 सीट मिली है। प्रदेश में भाजपा को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। भले ही भाजपा के प्रवक्ता सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन वे भी इस बात को मानते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना तय है। यह प्रभाव भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में है।

भाजपा को सबसे अधिक नुकसान पार्टी से अलग हुए पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के कारण हुआ है। हालांकि इस तरह की स्थिति का सामना भाजपा पूर्व में भी कर चुकी है। लेकिन हमेशा सबक न लेने और अपने नेताओं को कमतर आंकने के कारण भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात का उदाहरण सबके सामने है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी, उत्तरप्रदेश में कल्याण सिंह और मध्यप्रदेश में उमा भारती के कारण भाजपा को काफी हानि हुई। यह बात दीगर है कि मध्यप्रदेश और गुजरात में नुकसान इतना नहीं था कि भाजपा कांग्रेस से पीछे रह जाती। फिर भी सीटों और वोटों के मामले में 2003 की तुलना में काफी बड़ा फर्क देखने को मिला था।

झारखंड और उत्तरप्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक नुकसान हुआ।सवाल यह है कि क्या बदली हुई परिस्थितियों भाजपा कोई सबक लेगी? क्या राष्ट्रहित के मददेनजर वह अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस को परास्त करने की रणनीति पर काम करेगी? क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में चार बड़े महत्व के राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मनोवैज्ञानिक रूप से हार चुकी कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव से संजीवनी मिली गई है। इस संजीवनी के सहारे वह भाजपा और अन्य विपक्षी दलों को कुछ समय तक जवाब देती रहेगी। कुछ समय के लिए भाजपा निश्चित तौर पर एक कदम पीछे आ गई है। भ्रष्टाचार, महंगाई और चीन के मुददे पर मुहं छुपाती कांग्रेस को कर्नाटक में जीत का मास्क मिल गया है।

अब कांग्रेस यही मुखौटा लगाकर अपने विरोधियों का सामना करेगी। भाजपा ने दक्षिणी मुहाने पर सरकार बनाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की थी। लेकिन नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्द्धा और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की ओछी मानसिकता के कारण कर्नाटक में लंबे समय तक उठा-पटक चलती रही। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए भाजपा को सिर-आंखों पर बैठाया था, उसी ने भाजपा को अपनी नजरों से गिरा दिया। राजनीति में, खासकर चुनावी राजनीति में नेता क्या सोचते हैं इससे अधिक यह महत्वपूर्ण है कि जनता क्या सोचती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भाजपा नेताओं को दक्षिण में अपने एकमात्र किले के हाथ से जाने का दर्द है? क्या भाजपा के बड़े कद वाले नेता अपना मन बड़ा करने के लिए तैयार हैं? उमा भारती और कल्याण सिंह की ही तरह बाबूलाल मरांडी, येदियुरप्पा और गुजरात के नेता पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जैसे कई नेता हैं जिन्हें भाजपा से अलग होकर लाभ तो नहीं मिला, लेकिन पार्टी को काफी नुकसान हुआ। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि भाजपा के बड़े नेताओं ने हंसते-हंसते इस नुकसान को लंबे समय तक देखा। उन्हें कोई मलाल नहीं हुआ। आपसी अहं और प्रतिस्पर्द्धा के कारण उन्होंने जनता की नजरों में एक-दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे कई अवसर आए जब भाजपा ने अपनों को छोड़ परायों को गले लगाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विचारक के एन गोविन्दाचार्य भी एक ऐसा ही नाम है। जिन्हें दूसरे दल के नेता तो तवज्जो देते हैं, लेकिन भाजपा नेता ही उन्हें अपना नहीं मानते। आम धारणा तो यही है कि गोविन्दाचार्य जैसे नेता अगर भाजपा जैसे स्थापित और बड़े संगठन के माध्यम से अपना योगदान दें तो परिणाम दूरगामी और असरकारक होगा।

खैर ! कर्नाटक चुनाव से एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस चाहे कुछ भी करती रहे, देशभर में उसकी पैठ है। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी जनाधार है। भ्रष्टाचार, महंगाई या किन्हीं और कारणों से थोड़ा-बहुत अन्तर जरूर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि कांग्रेस का आधार खत्म हो जाये। देश और प्रदेश में कांग्रेस का एकछत्र राज भले न रहा हो, लेकिन वह सरकार बनाने का एक सशक्त विकल्प तो है ही। यही कारण है कि मनमोहन सिंह और राहुल-सोनिया गांधी जैसे जनाधारविहीन नेताओं के रहते भी कांग्रेस का आधार बरकरार है। ऐसे एक नहीं अनेक अवसर आए जब देश में कांग्रेस के खिलाफ जबर्दस्त माहौल देखा गया। लेकिन संगठित और सक्रिय प्रतिपक्ष न होने के कारण कांग्रेस को जनता ने बक्श दिया। कई चुनावों में भाजपा के नकारात्मक वोट कांग्रेस को मिले हैं। कर्नाटक चुनाव में भी यही हुआ। वहां जातीय प्रभाव और भाजपा के नकारात्मक मतों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो गया। भाजपा के राजनीतिक प्रबंधक असफल सिद्ध हुए। जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ में दे दी।

अब जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनना तय हो चुका है, भाजपा को सबक लेने और चेत जाने का वक्त आ गया है। अगर बड़े नेताओं ने बड़प्पन नहीं दिखाई, बिछुड़े नेताओं को नहीं अपनाया, अपना अहं नहीं त्यागे और कार्यकर्ताओं के महत्व को नहीं समझा तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी ऐसा ही हश्र हो तो कोई आश्चर्य नहीं। भाजपा के लिए एक सबक यह भी है कि किसी एक नेता पर आश्रित होने की बजाए सामूहिक नेतृत्व को स्थापित करे। नरेन्द्र मोदी हों या कि शिवराज सिंह चैहान - इनके नाम पर हवाई किले बनाने की बजाए मध्यम दर्जे के नेताओं को भी अग्रिम पंक्ति में लाने की कवायद जरूरी है। संगठन को किसी भी कीमत पर सत्ता का अनुचर बनने से अगर भाजपा रोक पाई तभी वह जनता और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरी हो सकती है। भाजपा की सफलता के लिए यह जरूरी है कि वह समन्वय और संवाद को भाषणों और किताबों से परे जमीन पर उतारने की दिशा में प्रयास करे। राजनीति में मीडिया और प्रचार की भूमिका तो है, लेकिन सीमित है। सिर्फ इसी के भरोसे न तो नरेन्द्र मोदी और न ही शिवराज देश के नेता बन सकते हैं। भाजपा में देश का नेता बनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बनाने वालों की कमी हो गई है। भाजपा में ऐसे नेताओं को भी आगे आने की जरूरत है जो पर्दे के पीछे रहकर अपने नेताओं को देश का नेता बनाएं। इस काम में निजी एजेंसियों से अधिक संगठन की भूमिका है। देश का नेता बनाने में निजी एजेंसियों और सत्ता की भूमिका जितनी बढ़ती जायेगी भाजपा पीछे और कांग्रेस आगे बढ़ती जायेगी। भाजपा के लिए कर्नाटक चुनाव का यह भी एक सबक है।

कर्नाटक चुनाव ने आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस को नहीं,भाजपा को कई सबक दिए हैं। सिर्फ पार्टी हित में ही नहीं बल्कि देश हित में भी यह जरूरी है कि भाजपा सबक सीखे और चेते।

विज्ञापन टैरिफ

जनवरी 2013 से लागू

तकनीकी विवरण

आवधिकता- साप्ताहिक(हर महीने 7,14,21,28 तारीख को प्रकाशित)

पृष्ठ- 8

पृष्ठ आकार- 37 से.मी. ×24 से.मी.

मुद्रण- आफसेट

विज्ञापन दरें

प्रति से.मी.कॉलम- 500

चौथाई पृष्ठ- 7,500 रुपए

आधा पृष्ठ- 15,000 रुपए

पूरा पृष्ठ- 30,000 रुपए

रंगीन- 25 प्रतिशत अतिरिक्त

अंतिम पृष्ठ- 50 प्रतिशत अतिरिक्त

प्रथम पृष्ठ- (अधिकतम 3 कॉलम 10 से.मी.) 100 प्रतिशत अतिरिक्त

वर्गीकृत

अधिकतम 30 शब्द तक 50 रुपए और

30 शब्दों से अधिक प्रति शब्द पांच रुपए

एक दिन- 250 रुपए

एक महीने- 5000 रुपए

पैनल- 500 रुपए

पैनल मासिक- 10000 रुपए

शासन की सख्ती ने बदला मनरेगा पर केन्द्र का नजरिया

-देवेन्द्र जोशी-

मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के बेहतर अमल से जहाँ ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदली है, वहीं जरूरतमंद ग्रामीण श्रमिकों को पिछले 6 वर्ष में 14972.75 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। मनरेगा कार्यों की पारदर्शिता, निगरानी और शिकायतों के निवारण की प्रभावी व्यवस्था कायम की गई है। इसके साथ ही मनरेगा लोकपाल भी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में मनरेगा में रोजगारमूलक कार्यों के लिए इसी माह एक अप्रैल से ई-मस्टर का उपयोग शुरू किया गया है। सभी निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारियाँ तथा भुगतान की कार्यवाही भी इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही सम्पन्न हो रही है। इस मकसद से इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ियों की गुंजाइश नहीं रह गयी है।

मनरेगा कार्यों की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर सर्तकता सेल का गठन कर मुख्य सर्तकता अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पृथक से संचालनालय का गठन किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण विकास कार्यों के सर्वेक्षण का सघन अभियान चलाया गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक उपयोग की स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण का व्यापक ब्यौरा संकलित करने में मदद मिली है।

प्रदेश में मनरेगा के जरिये ग्रामीण अंचलों में चलाये जा रहे रोजगार कार्यक्रमों के सुचारु क्रियान्वयन के मकसद से मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए लेबर बजट तैयार किया गया है। लेबर बजट के जरिये मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4438 करोड़ रुपये की राज्य-स्तरीय कार्य-योजना पर अमल सुनिश्चित किया जायेगा। इस नई पहल से प्रदेश के क्रियाशील करीब 67 लाख कार्य जॉब-कार्डधारी ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए ग्रामवार कार्य-योजना पर सुचारु अमल हो सकेगा। लेबर बजट की तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश में गत वर्ष माह नवम्बर 2012 में आयोजित ग्राम पंचायतवार बेस लाइन सर्वे के जरिये क्रियाशील तथा अक्रियाशील जॉब-कार्डधारियों की पहचान की गई है। जॉब-कार्डों को अद्यतन करने की इस मुहिम के बाद प्रदेश में करीब 53 लाख अक्रियाशील जॉब-कार्ड निरस्त किए गए हैं। अक्रियाशील जॉब-कार्डधारकों द्वारा पंजीयन के बाद पिछले 3 वर्ष में एक भी दिन मनरेगा में काम नहीं किया गया है, न ही उन्हें किसी कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया है। अक्रियाशील जॉब-कार्ड की निरस्तीकरण से अब वास्तविक क्रियाशील जॉब-कार्डधारकों के रोजगार और भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ और बेहतर रूप से सम्पन्न होंगी।

मध्यप्रदेश में मनरेगा के बेहतर अमल संबंधी तथ्य हाल ही में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भी सामने आये हैं। इसमें प्रदर्शित तथ्य यह दर्शाते हैं कि मध्यप्रदेश का परफार्मेंस अन्य कई राज्यों की तुलना में बेहतर है। रिपोर्ट में दर्शाये विभिन्न बिन्दुओं पर प्रदेश में त्वरित अमल कर पालन किया गया है। मनरेगा में सामुदायिक उपयोग की स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। यहाँ 58 फीसदी स्थायी परिसम्पत्तियाँ निर्मित हुई हैं। मनरेगा में 68 फीसदी निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं। ग्रामीण अंचलों में माँग के अनुसार रोजगार मुहैया करवाने की प्रभावी पहल हुई है। प्रदेश में मनरेगा कार्यों के बेहतर अमल के लिए 1796 उप यंत्री तथा 19 हजार 400 ग्राम रोजगार सहायक की संविदा नियुक्ति हो चुकी है। मनरेगा में जिला-स्तर पर 60:40 के श्रम-सामग्री का अनुपात सुनिश्चित किया गया है। कार्यों के भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाने की सामान्य स्तर की कुछ ही शिकायतें सामने आई हैं। शहडोल जिले की एमआईएस एन्ट्री न हो पाने से संबंधित समस्या का माह सितम्बर 2012 में ही समाधान किया जा चुका है।

मनरेगा के जरिये प्रदेश में अब तक 2 लाख 60 हजार 360 कपिलधारा कूप का निर्माण हो चुका है तथा 83 हजार 583 कूप का निर्माण प्रगति पर है। सभी कूप का विवरण पटवारियों द्वारा खसरा-खतौनी में आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है। प्रदेश में इन कूप से 3 लाख 90 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई का लाभ मिला है।

विजय शाह की बर्खास्तगी गहरा षड़यंत्र

(पेज एक का शेष भाग)

बंगारू लक्ष्मण को महज एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। जबकि हिंदुस्तान पर शासन करने वाले नेता अब तक देश पर अपनी असफल नीतियों से अरबों रुपए का कर्ज थोप चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को नोट कांड में जेल जाना पड़ा और तब भाजपा हाईकमान ने उन्हें भाग्य भरोसे छोड़ दिया। स्व. बलिराम कश्यप आदिवासियों को लामबंद करते हुए अलग थलग पड़ गए। ईमानदार और साफ चरित्र वाली महिला नेत्री मीना सिंह को बिजली घोटाले को उजागर करने वाली नोटशीट लिखने के कारण मंत्रिपद से हाथ धोना पड़ा। सांसद रह चुके गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी को तो पार्टी ही छोड़नी पड़ी थी।

आदिवासियों के शोषण की खबरों ने ही अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पैर जमाने का मौका दिया। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लौटाने के लिए नए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सलवा जुडूम अभियान चलाया। इस अभियान के कारण नक्सलवादियों से जूझते हुए कई आदिवासी मारे गए और उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। आदिवासियों को संकल्प दिलाकर वापस हिंदू धर्म में लौटाने वाले दिलीप सिंह जू देव जैसे तूफानी नेता भी खामोश हैं क्योंकि भाजपा को अब आदिवासियों को अपने कैंप में रोके रखने में कोई रुचि नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुवेल उरांव भी आदिवासियों के साथ हो रहे इस बर्ताव से वाकिफ हैं लेकिन वे कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। आज स्वाधीनता संग्राम से सेनानी रहे बिरसा मुंडा और टंट्या भील को मध्यप्रदेश की पहचान बनाने वाले विजय शाह कूटनीतिक षड़यंत्र के तहत दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किए गए हैं तब भाजपा के दिग्गज नेता खामोशी ओढ़े बैठे हैं। नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं कि विजय शाह को सार्वजनिक तौर पर इस तरह का मजाकिया संवाद नहीं करना चाहिए था।

इससे पहले जब आदिवासी नेता रेलम चौहान को महिला आयोग से हटाया गया था तब किसी ने न सोचा था कि भाजपा की राजनीतिक चालें कांग्रेस की बिछाई बिसात पर खेली जा रही है। उधर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सभी 47 विधानसभा सीटों पर आदिवासियों को रिझाने पटाने का अभियान चला रखा है। भूरिया के परम प्रिय सखा और राजनीतिक सहयोगी राजेन्द्र सिंह गेहलोत पूरे प्रदेश में दौरे करके आदिवासियों को लामबंद करने में जुटे हैं। उनके एक अन्य सहयोगी शांतिलाल पड़ियार आदिवासी समूहों को राजनीतिक बल देकर कांग्रेस के लिए अपना खोया जनाधार जुटाने में जुटे हैं। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा के कोर ग्रुप में घुसपैठ जमा चुके सत्ता के दलाल भाजपा के आदिवासी वोट बैंक को काटने की मुहिम सफल करते जा रहे हैं। कभी कांग्रेस का वोट बैंक कहे जाने वाले आदिवासियों का विश्वास जीतकर उन्हें भाजपा में लाने वाले वनवासी कल्याण परिषद, उसे जुड़े ग्रामभारती विद्यालय ,भाजपा का अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा सभी के कार्यकर्ता इन दिनों उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

सत्ता किसी भी राजनैतिक दल की हो आदिवासी बालिकाओं का शोषण, आदिवासी इलाकों में जहरीली शराब की बिक्री, वनोपज जुटाने वाले आदिवासियों को कम मेहनताना, वन भूमियों से बेदखली जैसी तमाम शोषणवादी नीतियां जारी हैं। आदिवासी छात्रावासों की दुर्दशा किससे छिपी है।

मध्यप्रदेश भाजपा ने आदिवासी इलाकों में जो संगठन मंत्री भेजे वे जनाधार बढ़ाने के बजाए चंदा बटोरने में जुट गए। सड़क पर बैठकर जूते जोड़ने वाले, और नगर पालिका में प्लंबर का काम करने वालों को भाजपा ने आदिवासी इलाकों में संगठन मंत्री बनाकर भेजा। उन्हें एक एक करोड़ रुपए चंदा दिलाया गया इस राशि से उन्होंने आदिवासियों के हित संवर्धन न करके खुद का भवन निर्माण का कारोबार खड़ा कर लिया। ये जानकारियां भाजपा संगठन तक पहुंचीं लेकिन संगठन के दिग्गजों ने इन सूचनाओं पर आंखें मूंद लीं और कान बंद कर लिये क्योंकि वे भी आदिवासी विरोधी षड़यंत्र के मोहरे ही थे।

आज जब एक बार फिर उजागर हो गया है कि विजय शाह की विदाई के पीछे आदिवासी विरोध का वही राजनीतिक षड़यंत्र काम कर रहा है तब जरूरी है कि मध्यप्रदेश के मूल निवासी आदिवासी नेता अपने राजनीतिक विकल्प पर एक बार फिर नए सिरे से विचार करें।

जन न्याय दल जैसे नवोदित राजनीतिक दल ने पिछड़ों और वंचितों को सत्ता में भागीदारी दिलाने की टेर लगाई है। यह दल विकास की दौड़ में पिछड़ने वाले वंचितों को मध्यप्रदेश में सत्ता सौंपने के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि वर्ष 2013 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आदिवासी वोट बैंक की खींचतान एक बार फिर तेज हो गई है। जाहिर है कि लगातार छले जाने वाले आदिवासी नेता अपने नए राजनीतिक विकल्पों पर भी विचार जरूर करेंगे।

दरवाजे पर दीदी की दस्तक

(पेज 2 से जारी आलेख का शेष भाग)

भी जीत सकने वाले चुनाव क्षेत्र से टिकिट न मिलना भी तय है। देश में यही दोनों राज्य ऐसे हैं जहाँ उमाभारती जानी जाती हैं, और दोनों ही जगहों से उन्हें बेदखल कर दिया गया है।

जिन गडकरी से उमाजी को कुछ भरोसा था वे अब भाजपा के अध्यक्ष पद से विदा हो चुके हैं, और उन्हें अध्यक्ष पद पर पुनर्प्रतिष्ठित करने की इच्छा रखने वाले संघ के लोगों का भी दबदबा कम हुआ है। ऐसे में तय है कि मुँहदेखी बात करने वाले नेताओं वाली पार्टी में उमा भारती की हालत मदन लाल खुराना की तरह हो जाने वाली है। पर युवा उमा भारती ने जीवन भर संघर्ष से मुँह नहीं मोड़ा और आगे भी नहीं मोड़ेंगीं। उनके प्रदेश में उनसे असंतुष्ट सुषमा स्वराज को सुरक्षित क्षेत्र दे दिया गया है, ऐसे में देखना होगा कि वे अपने प्रदेश के वात्सल्य से कब तक दूर रह सकेंगीं?

जिंदादिल लोगों के
जांबाज अखबार
जासूस बादशाह को
अक्षय तृतीया के
शुभअवसर पर
हार्दिक शुभकामनाएं।
एक शुभेच्छु

मध्यप्रदेश में झुग्गी माफिया को पनपने नहीं दिया जायेगा : शिवराज सिंह चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के खजराना मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन समारोह को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में झुग्गी माफिया को पनपने नहीं दिया जायेगा। समारोह में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया, सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन और महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे भी उपस्थित थे।

श्री चौहान ने बताया कि अवैध कालोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जा रही है। गरीबों के लिये सरकार भूमि आरक्षित करने की कार्यवाही भी करेगी। उन्होंने कहा कि जो गरीब जहाँ रह रहा है, वह वहीं रहेगा। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना के पूरा होने से नर्मदा का जल इंदौर में पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों को एक जून से एक रुपये प्रति किलो गेहूँ, दो रुपये प्रति किलो चावल और एक रुपये प्रति किलो आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध करायेगी। युवाओं का आव्हान करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना का लाभ उठाने को कहा। युवा उद्यमी बनेंगे तो मध्यप्रदेश का तेजी से विकास होगा।

मध्यप्रदेश में अटल ज्योति अभियान ने भाजपा का उत्साह बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की विकास एवं कृषि विकास दर तेजी से बढ़ी है, जिससे मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय-स्तर पर एक नई पहचान कायम हुई है। उन्होंने कहा कि गरीब बेटे-बेटियों को भी अच्छी शिक्षा मिले, ऐसे प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि खजराना मंदिर परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों पर एक करोड़ 76 लाख रुपये और व्यय होंगे। अभी इसके अधोसंरचना विकास पर 2 करोड़ 62 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। समारोह में श्री चौहान ने 42 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस क्षेत्र में हितग्राहियों को बड़ी संख्या में शासकीय योजनाओं का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, वह आगे भी जारी रहेगा। श्री महेन्द्र हार्डिया ने नर्मदा का जल क्षिप्रा में शामिल कराने के मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना लाने की योजना को उन्होंने अभिनव बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने आयोजन-स्थल पर विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह में विधायक सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, श्रीमती मालिनी गौड़ सहित अनेक जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने की तैयारी

भोपाल। अक्षय तृतीया अथवा आखा तीज-13 मई को बाल विवाहों को रोकने के लिए सभी जिलों को सतर्क कर दिया गया है। राज्य शासन ने जिला कलेक्टरों को बाल विवाह की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। इस दिन होने वाले सामूहिक विवाह समारोह पर शासन की पैनी नजर रहेगी। अक्सर आखा-तीज पर सामूहिक विवाह की आड़ में कुछ बाल विवाह भी हो जाते हैं।

एस्सेल बिजली वितरण कंपनी ने जनता से किया धोखा

जन न्याय दल हाईकोर्ट में लगाएगा जनहित याचिका

भोपाल। राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने सागर के बिजली उपभोक्ताओं को अजीब धोखाघड़ी के दुष्चक्र में फंसा दिया है।सरकार के प्रभावशाली लोगों के दबाव में बिजली कंपनी ने निजी क्षेत्र की जिस एस्सेल विद्युत वितरण (प्रा.) लिमिटेड को इकतरफा आर्थिक लाभ दिलाने वाला अनुबंध किया है वह अनुबंध की परिभाषा में साफ तौर पर धोखाघड़ी है। जन न्याय दल ने इस अनुबंध को निरस्त कराने के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करने का फैसला लिया है। जन न्याय दल अदालत में तो इस संबंध में सभी तथ्य पेश करेगा ही साथ में मध्यप्रदेश के आम नागरिकों से धोखाघड़ी करने वालों को सबक सिखाने की अपील भी करेगा।

जन न्याय दल के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंघई ने बताया कि इस संबंध में दल ने मध्यप्रदेश शासन और विद्युत कंपनी को नियमानुसार धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वैधानिक नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में निष्पादित हुए अनुबंध की शर्तें जन विरोधी व इकतरफा हैं। जिससे शासन व जनता के अमूल्य राजस्व की क्षति हो रही है ये शर्तें एस्सेल कंपनी को लाभ दे रहीं हैं। ये शर्तें व्यवस्था की आड़ में आम उपभोक्ताओं से लूट की खुली छूट देने वाली भी हैं। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर सागर में अपनी व्यावसायिक गतिविधियां

ऊर्जा मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सागर जाकर सांसद भूपेन्द्र सिंह और विधायक शैलेन्द्र जैन का अनशन तुड़वाया।

संचालित कर रही एस्सेल कंपनी से पीड़ित सागर की जनता इसका पुरजोर विरोध करते हुए यह अनुबंध निरस्त करने की मांग कर रही है। जिसके समर्थन में सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। विषय की गंभीरता इससे भी स्पष्ट होती है कि सत्तारूढ़ भाजपा के स्थानीय सांसद और विधायक को अपनी सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। इसके बाद भी सरकार के प्रभावशाली लोग जनहित के विरुद्ध अपरिहार्य कारणों से एस्सेल कंपनी को बचा रहे हैं। जिससे स्पष्ट है कि यह ठेका भारी भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए दिया गया है। इसीलिए इस ठेके की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जाना जनहित में आवश्यक है।

प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंघई ने बताया कि एस्सेल कंपनी के अधिकारी अपने अनुबंध के विपरीत जाकर सागर के उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क वसूल कर रहे हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार एस्सेल कंपनी को दिसंबर 2012 के बाद से विद्युत शुल्क वसूलना था परंतु कंपनी ने रिकवरी शुल्क जनवरी 2012 से लगाकर एक साल तक अवैध रूप से वसूला है। जिससे करोड़ों रुपयों की गैरकानूनी वसूली की गई है। इसी तरह एस्सेल कंपनी जो शुल्क अनुबंध कर्ता शासन को दे रही है वह भी दिसंबर 2012 के बाद का है।जबकि एस्सेल कंपनी ने जनवरी 2012 से विद्युत शुल्क उपभोक्ताओं से वसूला है। इसी तरह एस्सेल कंपनी की ओर से बिजली चोरी पकड़ने के बाद चुराई गई बिजली की रिकवरी निकालते समय उपभोक्ताओं के खाते में आलरेडी बिल्ड यूनिट नहीं घटाई जा रही है। उपभोक्ताओं के परिसर में लगे भार घंटों से गुणा कर मीटर की गणना की जा रही है। इस प्रकार तकनीकी जालसाजी से उपभोक्ताओं से आलरेडी बिल्ड यूनिट न घटाए जाने के कारण पैसा दोबारा लिया जा रहा है। जिसकी जांच विद्युत चोरी के संबंध में गणना पत्रक से की जा सकती है ये पूरी तरह से अवैध व शर्तों के विपरीत है।

श्री सिंघई ने बताया कि एस्सेल कंपनी की ओर से सागर में बड़ी तादाद में बिजली मीटर जबरिया बदले जा रहे हैं। नए मीटर एस्सेल कंपनी की ओर से स्वयं टेस्ट करके लगाए जा रहे हैं जबकि अनुबंध के अनुसार मीटर एमपीईबी की लैब में टैस्ट कर लगाए जाने हैं। इसी तरह एस्सेल कंपनी के अधिकारी इनपुट यूनिट बचाने के लिए बार बार इलेविन केवी फीडर को घंटों बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से चालू बिजली मीटरों को जबरन खराब घोषित कर एवरेज बिल से अधिक वसूली की जा रही है।

जन न्याय दल के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि शासन ने एक तीन सदस्यीय कमेटी घोषित की है जिसे एक माह में कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच कर शासन को रिपोर्ट देना है । जन न्याय दल का मानना है कि ये कमेटी एस्सेल कंपनी को संरक्षण देने एवं जनता के आक्रोश को ठंडा करने के लिए गठित की गई है। क्योंकि जब तक मूल अनुबंध की उच्च स्तरीय जांच नहीं की जाती और दोषियों के विरुद्ध संज्ञान नहीं लिए जाते तब तक जनता को शोषण से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अत: शासन ब्रीच आफ कंडीशन के आधार पर एस्सेल कंपनी का अनुबंध निरस्त करे।

स्वत्वाधिकारी ,मुद्रक,प्रकाशक आलोक सिंघई ने सम्यक प्रिंटर्स से छापा और ऊपरी भूतल-7 अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1,एमपी नगर भोपाल से प्रकाशित किया।
संपादक - आलोकसिंघई *फो.2555007,मोबा.-9425376322 न्याय क्षेत्र भोपाल.* ***Jasoos1967@yahoo.com***